विकासशील एवं अल्पविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं विशेषताएं (1)

भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विकासशील

अर्थव्यवस्था के रूप में आधारभूत विशेषताएँ अल्पविकसित का अर्थ %- P.E.D

'अल्पविकसित शब्द उन अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, जहाँ उस राष्ट्र के लोगों (जनता) का रहन-सहन का स्तर काफी नीचा होता है, क्योंकि वहाँ पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यकित आय का स्तर निम्न पाया जाता है। अल्पविकसित राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इन राष्ट्रों के पास अपनी गरीबी एवं कम आय के स्तर को ठीक करने का सामथ्र्य पाया जाता है। अल्पविकसित देशों को आर्थिक विकास के उपाय सुझाने के उंेश्य से नियुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के दल ने कहा है%-

हमें अल्पविकसित देश' शब्द के अर्थ को समझने में कठिनाई हुई है। हमने इस शब्द का प्रयोग उन देशों के अर्थ में किया है जिनकी प्रति व्यकित वास्तविक आय संयुक्त राज्य अमेरिका (न्ै।) कनाडा, आस्ट्रेलिया और पशिचमी यूरोप की प्रति व्यकित वास्तविक आय की तुलना में कम है। इस अर्थ में निर्धन देश' उपयुक्त पर्याय होगा।

अत% अल्पविकसित देश' सापेक्ष शब्द है। सामान्यत% वे देश जिनकी वास्तविक प्रति व्यकित आय संयुक्त राज्य अमेरिका (न्ै।) की एक चौथाई (() से कम है, अल्पविकसित देशों के वर्ग में रखे जाते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में आधारभूत विशेषताएं

भारतीय अर्थव्यवस्था एक कम आय स्तर की विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनसंख्या का एक चौथाई (() भाग दयनीय सिथति में जीवन.यापन करता है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को जानना अनिवार्य है जो कि इस प्रकार से हैं%-

(1) निम्न प्रति व्यकित आय - विकासशील देशों में प्रति व्यकित आय का स्तर काफी कम पाया जाता है। सन 2005 में भारत की प्रति व्यकित आय 720 डालर थी जोकि कुछ देशों को छोड़कर सबसे निम्न स्तर पर थी। 1990 से 2005 के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की गति कुछ विकसित देशों की तुलना में अधिक रही। फिर भी, प्रति व्यकित आय के तुलनात्मक अèययन से पता चलता है, कि विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था काफी पीछे है। उदाहरणार्थ% सन 2002 में, भारतीय प्रति व्यकित आय 480 डालर थी, जबकि (न्ै।) में 35060 डालर एवं न्.ज. में 25250 डालर थी।

(2) निम्न जीवन स्तर - संसार की लगभग तीन-चौथाई (3/4) जनसंख्या विकासशील देशों में निवास करती है, जिसके पास संसार की कुल आय के 1/5 भाग से भी कम आय होती है, जिसके कारण जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को अपना जीवन-यापन गरीबी, कुपोषण, बीमारी एवं अशिक्षा आदि में व्यतीत करना पड़ता है। इनके पास जीवन-यापन की आधारभूत आवश्यकताएँ जैसे रोटी, कपड़ा, एवं मकान की उपलब्धता नहीं

होती। सन 1999 में भोजन में कैलोरी की औसत मात्रा इन देशों में 2496 कैलोरी थी, जबकि विकसित देशों में 3400 कैलोरी थी। सन 2004-05 के अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग 28 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे (ठ.च.स) जीवन-यापन कर रही थी। विश्व विकास सूचकांक के एक अध्ययन के अनुसार भारत की 46 प्रतिशत शिशु जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। जनगणना 2001 के अनुसार, भारत में केवल 30 प्रतिशत गृहस्थों के पास अद्ध-स्थायी एवं 18 प्रतिशत के पास अस्थायी आवास सुविधाएँ उपलब्ध थीं। ग्रामीण क्षेत्रा में आवास सुविधाएँ शहरी क्षेत्रा की तुलना में काफी निम्न पायी जाती हैं। दसवीं योजना के एक आवासीय कार्य समूह दल के अध्ययन अनुसार लगभग 90 प्रतिशत कमजोर वर्ग के पास आवास सुविधाओं का अभाव था। इसलिए सरकार को इस समस्या के समाधान हेतु बड़े पैमाने पर कदम उठाने की आवश्यकता है।

(3) जनसंख्या वृ)ि की ऊँची दर - जनसंख्या की ऊँची वृ)ि दर के साथ निम्न उत्पादकता भारत में निम्न आय एवं निम्न रहन-सहन के स्तर का प्रमुख कारण है। जनसंख्या की तीव्र वृ)ि का अर्थ यह है कि प्रत्येक वर्ष आधारभूत आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा, मकान) की माँग में तीव्र वृ)ि होना। भारत में 1941.50 के मध्य जनसंख्या वृ)ि की दर 1.31 प्रतिशत थी जो कि 1991.2001 में बढ़कर 1.93% हो गई। सन 2000-2005 के मध्य यह गिरकर 1.5% हो गई। इसका प्रमुख कारण यह है कि 1991.2001 में जन्मदर 49 प्रति हजार से कम होकर 2005 में 24.8 प्रति हजार हो गई।

जनसंख्या की तीव्र वृ)ि दर के अन्तर्गत अच्छे रहन-सहन के स्तर को बनाए रखने हेतु तीव्र आर्थिक वृ)ि का होना अत्यन्त आवश्यक है। हालांकि तीव्र जनसंख्या वृ)ि दर श्रम शकित की आपूर्ति को बढ़ाती है, परन्तु माँग की अपेक्षा अधिक श्रमिकों की आपूर्ति के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

(4) बेरोजगारी एवं अल्प रोजगारी का ऊँचा स्तर - बेरोजगारी का स्तर अल्पविकसित देशों में ऊँचा है क्योंकि यहाँ पूँजी एवं विकास का स्तर निम्न पाया जाता है। ये देश अपनी श्रम शकित का कुशलता से प्रयोग नहीं कर पाते। इन देशों में जनसंख्या वृ)ि तीव्र होने से श्रम की आपूर्ति अधिक पाई जाती है तथा आर्थिक क्रियाओं का अभाव होने से श्रम की मांग अपेक्षाकृत निम्न होने से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में, कृषि क्षेत्रा में श्रमिकों का एक बड़ा भाग कार्यरत होता है जबकि आवश्यकता कम श्रमिको की होती है। अर्थात अतिरिक्त श्रमिकों का सीमान्त उत्पादन काफी कम, शून्य या ऋणात्मक पाया जाता है। इसलिए इस क्षेत्रा में छुपी हुई बेरोजगारी प्रचुर मात्रा में पायी जाती है। योजना आयोग ने छै के आंकड़ों के आधार पर दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में दैनिक चालू आधार पर एक अनुमान लगाया जिसके अनुसार 35 मिलियन लोग बेरोजगार थे। यदि बेरोजगार एवं अल्प रोजगार श्रमिको को मिला दिया जाए तो यह कुल श्रम-शकित का 9.21% हो जाता है, इसके साथ ही 2002.07 के मध्य लगभग 35 मिलियन व्यकित श्रम शकित से जुड़ गए। इस प्रकार भारत में खुली बेरोजगारी एवं अल्प-रोजगारी एक जटिल समस्या है जिसका समाधान भारतीय सरकार को दृढ़ इच्छाशकित से करना होगा।

(5) अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्रा का आधिपत्य - भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रा में निवास करती है तथा उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि होता है। सन 2004 में भारत में कार्यशील जनसंख्या का 58% भाग कृषि क्षेत्रा में कार्यरत था जो की राष्ट्रीय आय में लगभग 21% योगदान करता है। इसका अर्थ है कि 2ध्3 से 4ध्5 जनसंख्या की आजीविका कृषि क्षेत्रा पर निर्भर करती है। इसे हम निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर दर्शा सकते है।

प्रतिशत रूप में सक्रिय जनसंख्या का वितरण (2004)

(6) पूँजी निर्माण की निम्न दर - भारतीय अर्थव्यवस्था में पूँजी की कमी होना एक प्रमुख विशेषता अल्पविकसित देशों में पूँजी की कमी पाई जाती है। पूँजी निर्माण या निवेश की कमी के कारण कम उत्पादक जिससे कम आय स्तर जिससे बचत का स्तर निम्न जिससे पुन% पूँजी निर्माण या निवेश का स्तर निम्न प जाता है। इस प्रक्रिया को निर्धनता का दुश्चक्र कहा जाता है।

निम्नलिखित तालिका के आधार पर हम दर्शा सकते हैं कि भारत में विकसित देशों की तुलना में सकल पूँजी निर्माण कम पाया जाता है, इसलिए सकल पूँजी निर्माण के स्तर को रहन-सहन के अच्छे स्तर को बनाए रखने हेतु बढ़ाने की आवश्यकता है।

सकल पूँजी निर्माण तथा सकल घरेलू बचत, सकल, घरेलू उत्पाद (ळक्च्) के प्रतिशत रूप में

(7) परिसम्पत्तियों का दोषपूर्ण वितरण - भारतीय रिजर्व बैंक के जुलाई 1991 से जून 1992 तक के लिए ग्रामीण एवं शहरी परिवारों की परिसम्पत्ति के सर्वेक्षण से परिसम्पत्ति-वितरण में तीव्र असमानता विद्यमान होने का पता चलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 27% परिवारों, जिनकी सम्पत्ति 20000 रूपये से कम थी, के पास कुल परिसम्पत्तियों का केवल 2.4% था। इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग 51% परिवारों का कुल परिसम्पत्ति में भाग केवल 10% ही था। इसके विरु) 9.6% सम्) परिवारें, जिनमें प्रत्येक के पास 2.5 लाख रूपये से अधिक परिसम्पत्ति थी, के पास कुल परिसम्पति का 49% था।

भारत में परिवारों और परिसम्पत्तियों का प्रतिशत वितरण (1991-92)

स्रोत%- भारतीय रिजर्व बैंक, अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण, 1991-92 रिजर्व बैंक बुलेटिन मई 1999.

(8) उपभोग के सामाजिक आर्थिक सूचक - भारत में अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण मात्रा ही है%-

अल्पविकास की अभिव्यकित कई सामाजिक सूचकों द्वारा होती है अर्थात प्रति व्यकित कैलोरी उपभोग, प्रति हजार जनसंख्या के लिए डाक्टर, मोटर गाड़ियों, टेलीफोनों या टी.वी. सेटों की मात्रा इत्यादि। निम्न तालिका में कुछ चुने हुए देशों के लिए दिए गए आंकड़ो से पता चलता है कि भारत रहन-सहन के स्तर के सूचकों की दृष्टि से विकसित देशों से बहुत पीछे है। अशिक्षा की दर 2001 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 35% की तुलना में विकसित देशों में 5% से भी कम पाई जाती है।

कुछ चुने हुए देशों के रहन-सहन के समाजार्थिक सूचक (1999)

एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, पिछले पाँच दशकों के विकास परिणामस्वरूप भारत अपनी सकल घरेलू उत्पाद (ळक्च्) की विकास दर, जो 1950.51से 1970.71 के दौरान 3.5% थी, बढ़ाकर 2000.01 से 2004.05 के दौरान 7% तक बढ़ा पाया है। तथापि, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, भारत का स्थान विश्व में 127 वे नम्बर पर है। इसका रिकार्ड कुपोषण को दूर करने में खराब है क्योंकि कुल-जनसंख्या का 46% कुपोषण का शिकार है 2001 की जनगणना के अनुसार केवल 52% जनसंख्या के पास स्थायी मकान है और केवल 36% जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल प्राप्त हैं। चाहे गरीबी की दर कम होकर 26% हो गई है। तब भी 26 करोड़ व्यकित गरीब हैं और इस प्रकार गरीबी का बोझ अधिक है। बेरोजगारी की दर जो 2001.02 में 9.2% थी, बहुत ऊँची है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था ने बहुत से क्षेत्रो में सराहनीय प्रगति की है परन्तु गरीबी दूर करने, कुपोषण को नियंत्रित करने और समग्र जनसंख्या को आवास तथा सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने में अभी मीलो का सफर तय करना है।